



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2005/पौष 9, 1927

No. 333]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2005/PAUSA 9, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2005

**विषय :** चीन जन. गण. और थाईलैण्ड से बस और लॉरी/ट्रक के लिए बायस टायरों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 14/9/2005-डीजीएडी.—चूंकि ऑटोमोटिव टायर मैयुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए), नई दिल्ली (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. और थाईलैण्ड (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ट्रकों सहित बस और लॉरी के लिए बायस टायरों के पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

और चूंकि प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य विद्यमान है, यह प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की एतद्वारा जांच शुरू करते हैं।

### 1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद चीन और थाईलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरी (ट्रकों सहित) में प्रयुक्त नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक डायगोनल प्लाई या क्रास प्लाई नॉन रेडियल बायस टायर्स, रबड़ की ट्यूब्स और फ्लैप्स हैं। किसी टायर सेट में आमतौर पर एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप होता है। बाजार की शब्दावली में "टीटीएफ" (टायर + ट्यूब + फ्लैप) शब्द टायर सेट के अर्थ के रूप में प्रचलित है। टायर, ट्यूब और फ्लैप प्रत्येक की एक इकाई को ओटोमोटिव अनुप्रयोगों में एक साथ प्रयोग किया जाता है। वे संयुक्त रूप से "टायर" का कार्य करते हैं। बस और लॉरी/ट्रकों में प्रयुक्त नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक डायगोनल अथवा क्रास प्लाई नॉन रेडियल बायस टायर, ट्यूब और फ्लैप जिसे टीटीएफ आधार पर अथवा सेट में अथवा अलग-अलग करके टायर ट्यूब और फ्लैप के रूप में या किसी अन्य संहति के रूप में बेचा जाता है या आयात किया जाता है, इस आवेदन में विचाराधीन उत्पाद है।

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत रबड़ और इसके उत्पादों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है। टायर, ट्यूब और फ्लैप को अध्याय 40 के अंतर्गत एक एकल उप शीर्ष के अधीन संयुक्त रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। टायर, सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 40112090 के अंतर्गत आते हैं; ट्यूब, सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 40131020 और फ्लैप, सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 40139049 के अंतर्गत आती हैं।

### 2. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन, जन. गण. और थाईलैंड हैं।

### 3. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

आवेदन को मै. अपोलो टायर लि. और मै. सीट लि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का प्रयोग करते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) द्वारा दाखिल किया गया है। मै. जे के टायर्स (जे के इंडस्ट्रीज लि.), मै. बिरला टायर्स (केसोराम इंडस्ट्रीज लि.) और मै. एमआरएफ लि. ने आवेदन का समर्थन किया है। समर्थनकारी कंपनियों के साथ-साथ आवेदक कंपनियां संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन के 50% से भी अधिक हिस्से का उत्पादन करती हैं। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने निर्धारण किया है कि (क) संबद्ध वस्तु के आवेदक विनिर्माताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है; (ख) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन के 50% से अधिक के लिए आवेदन लेखे का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक; और (ग) आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से किया गया है।

उपर्युक्त की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि नियम 2 के अर्थ के भीतर समर्थनकारी कंपनियों के साथ आवेदक कंपनियां घरेलू उद्योग हैं और आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार अर्हता के मानदंडों को पूरा करता है।

#### 4. समान वस्तुएं

आवेदक ने दावा किया है कि इसकी सदस्य कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध कंपनियों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। आवेदक का दावा है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सूचना सेवा (आईबीआईएस), मुम्बई द्वारा संकलित आयातों से संबंधित सूचना उपलब्ध करायी है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति की गई वस्तु एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा रही है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### 5. सामान्य मूल्य

आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला व्यवहार दिया जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने पैरा 7 के अनुसार श्रीलंका की बाजार अर्थव्यवस्था वाले एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में प्रस्ताव किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का परिकलन श्रीलंका में कीमत के आधार पर किया गया है जिसे चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य के उपयुक्त अनुमान के रूप में बिक्री और वितरण संबंधी बंधे खर्च के रूप में यथोचित रूप से समायोजित किया गया है।

तथापि, अलग- अलग निर्यातक इस धारणा का खंडन कर सकते हैं और प्राधिकारी संगत नियमों के अनुसार अलग- अलग निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दावों की जांच करेंगे।

आवेदक ने बताया है कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे संबद्ध वस्तु की थाइलैंड में प्रचलित घरेलू कीमतों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों और लाभों के लिए उचित बढ़ोत्तरी को शामिल करने के पश्चात निर्मित उत्पादन लागत के आधार पर थाइलैंड में सामान्य मूल्य का दावा किया है। कीमत निर्धारित करते समय प्रमुख कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया है।

**6. निर्यात कीमत**

संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस तथा आईबीआईएस आंकड़ों पर विचार करके किया गया है। कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत पर पहुँचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभार एवं बैंक प्रभारों के आधार पर दावों को समायोजित किया गया है। ऋण लागत तथा अप्रत्यक्ष करों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा समायोजन का दावा किया गया है जिसे इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया है।

**7. पाटन मार्जिन**

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य इन देशों से निवल निर्यात कीमतों की तुलना में काफी उच्चतर हैं जो प्रथम दृष्टया यह संकेत करता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा पाटन किया जा रहा है।

**8. क्षति तथा कारणात्मक संबंध**

आवेदन ने घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के संबंध में विभिन्न मापदण्डों पर सूचना उपलब्ध कराई है। बाजार हिस्से में कमी; स्थिर बिक्री; निरपेक्ष रूप से तथा उत्पाद की मांग के संबंध में, दोनों रूप में आयात की मात्रा में वृद्धि; अत्यधिक कीमत कटौती; कम कीमत पर बिक्री; कीमत ह्रास; लाभ में कमी; निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह; समग्रतः तथा संचयी रूप से माल सूची में वृद्धि जैसे मापदण्ड प्रथम दृष्टया यह इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठाई है। आवेदक ने आयात में वृद्धि की दर में तेजी, संबद्ध देशों में अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमता तथा पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती के आधार पर वास्तविक क्षति के खतरे का दावा भी किया है।

**9. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा तथा प्रभाव हेतु पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

**10. जांच अवधि**

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2004 से 31 जून, 2005 (15 महीने) तक की है। तथापि क्षति जांच अवधि में 2001-2002 से 2003-2004 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल रहेगी।

**11. सूचना प्रस्तुत करना**

संबद्ध देशों के निर्यातकों, दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, इस जांच से संबंधित ज्ञात आयातकों तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को अवगत कराने के लिए अलग से लिख जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार  
कमरा सं.-240, उद्योग भवन,  
नई दिल्ली - 110011

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों, जो पाटन, क्षति तथा कारणात्मकता के संबंध में जांच से संबंधित सूचना उपलब्ध करा सकते हैं, को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

## 12. समय सीमा

### (क) सामान्य समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों, जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, को अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित है। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध, जो भी हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

### (ख) बाजार अर्थ-व्यवस्था वाले तृतीय देश के चयन के लिए विशिष्ट समय-सीमा

जांचाधीन हितबद्ध पार्टियाँ श्रीलंका को चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के पैरा-5 में यथा उल्लिखित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के रूप में परिकल्पित किए जाने की उपयुक्ता पर टिप्पणी कर सकती हैं। ये टिप्पणियाँ इस अधिसूचना को प्रकाशित किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

## 13. सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, हितबद्ध पार्टियों को, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना के अगोपनीय सार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाली पार्टी के मत में ऐसी सूचना संक्षेपीकरण के लिए सुग्राह नहीं है तो तत्संबंधी कारण संबंधी विवरण उपलब्ध करना अपेक्षित है। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

## 14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें हितबद्ध पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**  
New Delhi, the 30th December, 2005

**Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Bias Tyres for Bus and Lorries/Trucks from China PR and Thailand.**

**FINO.14/9/2005-DGAD:— WHEREAS** Automotive Tyre Manufacturer's Association (ATMA) New Delhi, (herein after referred to as applicant) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as. the Rules), alleging dumping of Bias Tyres for bus and lorries including trucks (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from the Peoples Republic of China and Thailand (herein after referred to as subject countries) and requested for initiation of anti dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.

**AND WHEREAS**, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, this Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

The product under consideration in the present application is New/ Unused Pneumatic Diagonal Ply or Cross Ply Non Radial Bias Tyres, Tubes and Flaps of rubber used in buses and lorries (including trucks) originating in or exported from China and Thailand. A tyre set generally comprises of one Tyre, one Tube and one Flap. In the market parlance the term "TTF" (Tyre+Tube+ Flap) is prevalent to denote the tyre set. One unit each of Tyre, Tube and Flap is used together in automotive applications. They jointly render the function of "Tyre". New/ Unused Pneumatic Diagonal Ply or Cross Ply Non Radial Bias Tyres, Tube and Flap used

in bus and lorries/trucks, sold or imported either on TTF basis or in Set or individually as Tyre, Tube and Flap or in any other combination, constitutes the product under consideration in the present application.

Product under consideration is classified under Chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975 under the category of Rubber and Articles thereof. Tyre, Tube and Flap are not jointly classified under a single subheading under Chapter 40. Tyres falls under customs subheading no. 40112090, Tubes falls under customs subheading no. 40131020 and Flaps falls under customs subheading no. 40139049.

## 2. COUNTRIES INVOLVED

The countries involved in the present investigation are People's Republic of China and Thailand.

## 3. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

The application is filed by Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) on behalf of the domestic industry using the information provided by M/s Apollo Tyres Ltd and M/s Ceat Ltd. Application has been supported by M/s JK Tyres (JK Industries Lt), M/s Birla Tyres (Kesoram Industries Ltd) and M/s MRF Ltd. Applicant companies alongwith supporting companies constitute more than 50% of Indian production of the subject product. On the basis of the information available on record the Authority has determined that (a) production of the applicant manufacturers of the subject goods constitutes a major proportion in Indian production; (b) domestic producers expressly supporting the application account for more than 50 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry; and (c) the application has been made on behalf of the domestic industry.

The Authority after examining the above, determines that the applicant companies alongwith the supporting companies constitute domestic industry within the meaning of Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of Rules supra.

## 4. LIKE ARTICLES

The applicant has claimed that goods produced by its member companies are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. There is no significant difference in the subject goods produced by the domestic industry and those exported from subject countries. Applicant claims that the two are technically and commercially substitutable. Applicant has provided information on imports as compiled by Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Kolkatta and International Business Information Service (IBIS) Mumbai. Applicant has claimed that the subject goods and goods produced and supplied by the domestic industry is being interchangeably used. For the purpose of present

investigation, the goods produced by the domestic industry is being treated as Like Article to the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

#### 5. NORMAL VALUE

The applicant has claimed that China PR should be treated as non-market economy and normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. The domestic industry has proposed Sri Lanka as an appropriate third country market economy in terms of para 7. Accordingly normal value has been worked out on the basis of price in Sri Lanka duly adjusted for selling and distribution overheads as an appropriate estimate of normal value in China PR.

However, the individual exporters may rebut this presumption and the Authority shall examine the market economy claims of individual exporters in terms of the relevant Rules.

The applicant has stated that despite their best efforts they have not been able to obtain information about the domestic prices of the subject goods prevailing in Thailand. The applicant has claimed normal value in Thailand on the basis of constructed cost of production, after making reasonable addition for selling, general and administrative costs and profit. International prices of major raw materials have been considered while constructing the cost of production.

#### 6. EXPORT PRICE

Export price of the subject goods from the subject countries has been determined by considering DGCI&S and IBIS data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, port handling and port charges and bank charges to arrive at ex-factory export price. Adjustment has been claimed by the applicant on account of credit costs and indirect taxes, which has not been allowed at this stage.

#### 7. DUMPING MARGIN

There is sufficient evidence that normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices from these countries, indicating prima-facie that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject countries.

#### 8. INJURY AND CAUSAL LINK

Applicant has furnished information on various parameters relating to injury to the domestic industry. Parameters, such as decline in market share, stagnant sales, increase in volume of imports both in absolute terms and in relation to the demand



of the products, significant price under-cutting, price under-selling, price depression, decline in profits, return on investments and cash flow, increase in inventories, collectively and cumulatively prima-facie indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping from the subject countries. Applicant has also claimed threat of material injury on the grounds of increase in the rate of increase in imports, surplus unutilized capacities in subject countries and significant price undercutting by the dumped imports.

## 9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

## 10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2004 to 30<sup>th</sup> June 2005 (15 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2001-02 to 2003-04 and the POI.

## 11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries, their Government through the Embassy, the importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

Designated Authority,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce,  
Government of India,  
Room No. 240,  
Udyog Bhavan, New Delhi – 1100 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

## 12. TIME LIMIT

### a) General Time Limits

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

### b) Specific time limit for selection of market economy third country

Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of Sri Lanka which, as mentioned in the Para 5 above of this initiation notification is envisaged as a market economy third country for the purpose of establishing normal value in respect of the China PR. These comments must be submitted within two weeks from the date of publication of this notification.

## 13. SUBMISSION OF INFORMATION

In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

## 14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by interested parties.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority